दलित लड़की की मां ने मानवाधिकार आयोग से.....

पेज एक का शेष

महत्वपूर्ण है। बता दें कि पीड़ित लड़की की मां साफ तौर पर कह रही है कि पुलिसकर्मी कप्तान सिंह ने उनकी लड़की से बलात्कार की कोशिश भी की, जिसमें वह अमित के हाथों मारा गया। बेशक पुलिस महकमा दोनों पुलिसकर्मियों को शहीद बता रहा है लेकिन लड़की की मां और तथ्यों की गहराई में जाने पर संकेत मिल रहे हैं कि दोनों पुलिसकर्मी उस समय मारे गए, जब गाड़ी के अंदर बैठी लड़की के साथ किसी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। बाद में बुटाना गांव से कुछ अन्य लड़कियों को पुलिस द्वारा उठाने के मामले और उनके साथ हुए सुलूक से भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि बुटाना पुलिस के कुछ पुलिसवालों ने न सिर्फ इन दोनों लड़कियों बल्कि गांव की अन्य उठाई गई लड़कियों के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया जिन्हें बाद में पांच किलो ही देकर चुप करा दिया। इनमें ज्यादातर लड़कियां दलित परिवारों से हैं।

क्यों किया एनजीओ टीम का पीछा

मानवाधिकार आयोग की टीम के अलावा चंडीगढ़ से बेखौफ आजादी एनजीओ की महिला सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी बुटाना इस मामले की जांच करने और पीड़ित परिवार की आवाज उठाने के लिए पहुंचे। इस टीम ने बुटाना पुलिस चौकी में संजय का बयान लिया और उन्होंने पहले की ही तरह तमाम आरोपों को गलत बताया। इसके बाद यह टीम जब बरोदा पुलिस थाने जाने लगी तो संजय ने सिविल ड्रेस में उनका पीछा किया। बीच रास्ते में जब एनजीओ के लोगों ने अचानकर रोककर संजय से इस तरह पीछा किये जाने की वजह पूछी तो उसने कहा कि वह भी बरोदा थाने जा रहा है। इस पर एनजीओ टीम ने कहा कि क्या वह सिविल ड्रेस में थाने जा रहा है, उसकी वर्दी कहां है तो इस बात का संजय कोई जवाब नहीं दे सका। बता दें कि संजय बुटाना चौकी इंचार्ज है और पीड़ित दलित लड़की ने गैंगरेप करने का आरोप जिन पुलिसकर्मियों पर लगाया है, उसमें संजय का नाम भी शामिल है।

एनजीओ ने नौजवान भारत सभा से जुड़ी महिला नेत्री प्रवेश कुमारी और लड़की की मां का बयान लिया। इन लोगों ने भी गांव वालों से बातचीत की। प्रवेश कुमारी ने अपने बयान में कहा कि गैंगरेप की शिकार लड़की की मां ने बुटाना पुलिस चौकी के कुछ पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप के आरोप लगाए हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जिला प्रशासन और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में सारे तथ्य स्पष्ट हैं और वे पुलिसकर्मियों की बेगुनाही का सबूत नहीं देते हैं। इस मामले में पुलिस वालों ने कदम कदम पर जुल्म किए हैं। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उनका संगठन चैन से नहीं बैठेगा। प्रवेश कुमारी ने कहा कि चूंकि लड़की दलित है, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है।

भीम आर्मी ने किया किनारा

इस मामले में भीम आर्मी का पक्ष जानने के लिये जब उनके फ़रीदाबाद से एक नेता अंकुर सागर से उनके अध्यक्ष चन्द्रशेखर का फ़ोन नम्बर लेने के लिये सम्पर्क किया गया तो उन्होंने अध्यक्ष चन्द्रशेखर का फ़ोन नम्बर देने की बजाय शिकायत की कि आपने भाई चन्द्रशेखर के बारे में अपनी पिछली रिपोर्ट में कैसे लिख दिया कि वो इसलिये चुप बैठे हैं क्योंकि इस मामले में प्रसिद्धि नहीं मिलनी। बता दें कि इस मामले पर सोनीपत में धरना प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने भीम आर्मी के स्थानीय नेताओं से सम्पर्क किया था। लेकिन उन्होंने यह कहते हुये मना कर दिया था कि इसमें तो लड़की की ही गलती थी-वो रात में वहां क्यों गई थी? यानी उनकी और बीजेपी/आरएसएस की मानसिकता में कोई अन्तर नहीं है। क्या दलित महिलायें ऐसे लोगों से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में अपने साथ खड़े होने की उम्मीद कर सकती है?

अंकुर सागर ने मज़दूर मोर्चा को अगले दिन बताया कि भाई चन्द्रशेखर 31 तारीख को सोनीपत चुनाव में प्रचार करने के लिये आयेंगे जहां उनसे मिला जा सकता है। जब उनको बताया गया कि शुक्रवार को तो हमें ये खबर छापनी है तो उन्होंने भीम आर्मी/आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी से बात करने के लिये उनका नम्बर भेजा था। लेकिन मैसेज में नम्बर नहीं पहुंच पाने के कारण उनसे बात नहीं हो सकी।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

डब्ल्यूएचओ के दबाव में प्लाजमा थैरेपी को फेल घोषित करने की साजिश

गिरीश मालवीय

मैं शुरू से ही लिख रहा हूँ कि भारत का ICMR पूरी तरह से WHO और वैश्विक फार्मा कम्पनियो की गुलामी कर रही है आज ICMR ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को जल्द ही बंद किया जा रहा है। ICMR इस थेरेपी को कचरे के डिब्बे में डालने की तैयारी कर रहा है ICMR कह रहा है कि इस थेरेपी से मृत्युदर में कोई कमी नहीं आती। लेकिन यही ICMR कोरोना की सबसे महंगी दवा रेमेडीसीवीर के लिए अलग बिलकुल अलग एप्रोच अपनाता है जबकि रेमेडीसीवीर के बारे में भी यही कहा जाता है और इस बात पर तो WHO ने भी मुहर लगा दी है लेकिन इसके बावजूद भारत का ICMR इसे कोरोना की इलाज प्रक्रिया में शामिल रखे हुए है।

प्लाज्मा थैरेपी के बारे में WHO ने कभी भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया 10 अगस्त को ही मैंने लिखा था कि दुल्हिन वही जो पिया मन भाए और इलाज वही जिसपे WHO ठप्पा लगाए मुझे याद है लगभग 2 महीने पहले NDTV पर WHO वाली सौम्या स्वामीनाथन का इंटरव्यू था उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने प्लाजमा थेरेपी की बात की तो उन्होंने कोई इंट्रेस्ट ही नहीं लिया था उसमे, बात टाल दी थी मै तभी समझ गया था कि इनका इंट्रेस्ट इलाज में नहीं है बल्कि पैनिक क्रिएट करने और उसे सतत बनाए रखने में है। कोविड ग्रस्त होकर ठीक हुए सैकड़ों लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया और सरकार ने प्लाज्मा बैंक भी खोल दिया मुख्यमंत्री अपील कर रहे है कि आओ और प्लाजमा दो लेकिन अब कह रहे है कि प्लाजमा थेरेपी कारगर नहीं है, दरअसल ऐसा कन्फ्यूजन जान बूझकर क्रिएट करते है ये लोग ताकि बाद में आसानी से पलट सके, कि हमने तो पहले ही बोल दिया था , ICMR ओर एम्स तो वैसे भी इनके गुलाम बन ही चुके है

आज यही बात सच साबित हुई है ICMR के इस निर्णय से दिल्ली सरकार खासी नाराज है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे है कि आईसीएमआर-एम्स ने मिलके केस स्टडी शुरू की थी लेकिन उसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है. दिल्ली सरकार इसमें काफी आगे बढ़ चुकी है और ट्रायल हमने उन्हीं के परमिशन से शुरू की थी. परमिशन लेकर ही प्लाज़्मा दिल्ली में दिया जा रहा है. दिल्ली में दो हजार से ज्यादा प्लाज्मा लोगों की जान बचाने के लिए दिया जा चुका है. मैं खुद उदाहरण हूं, प्लाज्मा से मेरी जान बची है, मैं कहूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए.

दिल्ली में इसका फायदा होते हुए दिख रहा है दो हजार से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा बैंक के जरिए प्लाज्मा दिया गया और बहुत सारे लोगों ने खुद प्लाज्मा का इंतजाम किया वह अलग है. सिर्फ आईएलबीएस से दो हजार से ज्यादा प्लाज़्मा जारी किया जा चुका है. अमेरिका ने भी कहा कि प्लाज़्मा के फायदे हैं और रिसर्च पूरी दुनिया में चल रही थी अमेरिका में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना से लड़कर ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। इससे पहले चीन में फरवरी से ही इस मेथड के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। साफ है कि ICMR बिग फार्मा कम्पनियो के दबाव में आकर प्लाज्मा थेरेपी को फेल बता रही है यदि इसे फेल नहीं बताया जाएगा तो लोग Regeneron कम्पनी की नई एंटीबॉडी ड्रग REGN-COV को कैसे खरीदेंगे !

डीपीएस फरीदाबाद का...

पेज एक का शेष

के प्रिंसिपल वर्मा की खूब थू-थू हो रही है लेकिन जिला प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। आल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव कैलाश शर्मा ने इस आडियो के संबंध में प्रशासन और हरियाणा सरकार से कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिनों वर्मा के खिलाफ स्कूल गेट पर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। बता दें कि मॉर्डन डीपीएस में ओल्ड फरीदाबाद के भी कुछ सेठों का पैसा लगा हुआ है। लेकिन नीचे से ऊपर उठे इन सेठों को उस स्कूल में पढ़ने वाले मिडिल क्लास परिवारों की कोई फिक्र नहीं है।

मजदूर मोर्चा स्कूलों की इस खुली गुंडागर्दी के खिलाफ लगातार लिख रहा है। फरीदाबाद के तमाम स्कूल अप्रैल से लेकर अभी तक सभी बच्चों से ट्रांसपोर्ट फीस मांग रहे हैं। डीपीएस फरीदाबाद ने कुछ अभिभावकों से इस फीस की वसूली भी कर ली है। जिन बच्चों के अभिभावकों ने ट्रांसपोर्ट फीस मांगे जाने पर ऐतराज किया, उनके बच्चों के नाम स्कूल से काटे जाने की धमकी दी गई। इससे पहले अभिभावकों ने कई बार डीपीएस के प्रिंसिपल को ईमेल भेजा, वाट्सऐप पर संदेश भेजा लेकिन स्कूल की ओर से कभी किसी बात पर जवाब नहीं दिया गया।

आरोप है कि डीएवी पब्लिक स्कूल ने बच्चों के घरों पर अपने कर्मचारियों को भेजकर ट्रांसपोर्ट फीस मंगवाई। इस संबंध में डीएवी में पढ़ने वाले एक बच्चे के पिता ने सीधे हरियाणा के सीएम, पीएम और शिक्षा मंत्रालय को लिखा। उन्होंने लिखा - जब बैंक इस संकट में लोगों के घर ईएमआई मांगने नहीं जा सकते हैं फिर डीएवी पब्लिक स्कूल-14, सैक्टर, फरीदाबाद कैसे लोगों के घर फीस मांगने भेज रहा है। क्या सरकार और जिले के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि व स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करें। एक अभिभावक ने तो आरोप लगाया कि डीएवी स्कूल वालों ने ट्रांसपोर्ट फीस वसूलने के लिए बाउंसर्स तक घरों पर भेजे।

संघ-भाजपा का साथ, फिर भी नहीं आस

प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक फुटबॉल बनकर रह गए हैं। सरकार से लेकर अदालतों तक उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। सीबीएसई तक ने अभिभावकों की शिकायतों से पल्ला झाड़ लिया है। डीएवी स्कूल के एक बच्चे के अभिभावक ने सीएम से पूछा है कि - स्कूल के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों को हरियाणा सरकार नहीं सीबीएसई देखता है। जब सीबीएसई के पास जाते हैं तो वह कहता है राज्य सरकार देखेगी... कोई बताएगा ये स्कूल माफिया किसके तहत आता है।

लेकिन मिडिल क्लास के ये सारे अभिभावक कभी खुद से सवाल नहीं करते कि उन्हें किसने फुटबॉल बनाया है। स्कूलों के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले कई सारे अभिभावकों में आरएसएस की शाखा में जाने वाले स्वयंसेवक भी है। उनके ऊपर भाजपा सरकार की भक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है। वे सरकार से स्कूलों पर कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें लगता है कि सारी गलती स्कूलों की है, जबकि प्राइवेट स्कूलों को भाजपा सरकार ने ही संरक्षण दे रखा है। इन स्कूलों ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के नाम पर सरकार से सस्ती जमीन हासिल की थी। हरियाणा सरकार जब चाहे इनसे वो जमीन छीन सकती है। लेकिन न तो अभिभावक समझदारी दिखा रहे हैं और न ही वे लोग, जिनको उन्होंने वोट देकर पिछला चुनाव जिताया था।

सविता गर्ग का मामला

फरीदाबाद में रहने वाली सविता गर्ग को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी से मॉर्डन डीपीएस की शिकायत की है। सविता ने स्वामी को लिखा है कि उनका बेटा इस स्कूल में पढ़ता है। उन्होंने किसी तरह से अगस्त तक स्कूल की पूरी फीस भर दी है। लेकिन स्कूल ने अब 28 अक्टूबर 2020 तक आखिरी तारीख देते हुए कहा है कि पूरी फीस भरें नहीं तो छात्र का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। सविता गर्ग ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वामी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश (petition no.LPA 409/2020 dated 1.10.2020 titled as Amandeep Singh Vs State of Punjab & othr) का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत के आदेश में सिर्फ पूरी ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई है लेकिन स्कूल अन्य मदों की भी फीस मांग रहा है।

उन्होंने मॉर्डन डीपीएस पर कार्रवाई की मांग की है। आमतौर पर स्वामी इस तरह की शिकायतों का संज्ञान नहीं लेता। अलबत्ता कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ कोई शिकायत करे तो वह उसका संज्ञान फौरन लेते हैं। इस तरह सविता गर्ग की इस शिकायत का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

पुलिस के साये में बलात्कार

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

हाथरस कांड के बाद हरियाणा के सोनीपत में गोहाना-जींद मार्ग पर बुटाना गांव के नजदीक पुलिस कर्मियों द्वारा नाबालिग दलित लड़की का हैवानी उत्पीड़न व बलात्कार तथा लड़की के साथी अमित की हत्या की दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई। 'पुलिस के साये में बलात्कार!' में पुलिस पीड़ित की रक्षा व उसके सम्मान के कानून को ताक पर रखने और 'बुटाना मर्डर, गैंगरेप और एनकाऊंटर का सच वो नहीं जो पुलिस बता रही-मज़दूर मोर्चा ने मौके पर जाकर की पड़ताल', हत्या, एनकाउंटर और रेप में किसे कया मिला ?', 'वामपंथी दलों की अवसरवादिता' तथा दलितों के ठेकेदार भी महिला विरोधी' में पुलिसिया बलात्कार व एनकाउंटर की वास्तविकता को बेनकाब किया गया है।

मज़दूर मोर्चा के 18-24 अक्टूबर 2020 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक साहित्यिक व आर्थिक मुद्दों पर अनेक समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। हाथरस में दलित युवती से बलात्कार -हत्या के मामले से लोगों का ध्यान भटकाने तथा आरोपियों को बचाने के लिये मीडिया व जांच एजेंसियों द्वारा झूठ प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के विरुद्ध दंगे भड़काने व योगी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश और भीम आर्मी व पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के बीच सम्बन्ध होने तथा सौ करोड़ रुपये का विदेशी फंड आने जैसे झूठे प्रचार के बाद मीडिया व यूपी एसआईटी द्वारा जबलपुर मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर राजकुमारी बंसल को अर्बन नक्सली व 'भाभी' करार देने के झूठ का 'हाथरस में नक्सली कहे जाने वाली भाभी दरअसल एक संघर्षशील डॉक्टर है' में पदाफ़ाश किया गया है।

भीमा कोरेगांव से लेकर दिल्ली दंगे, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की 2016 की वारदात से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध धरने-प्रदर्शन और हाथरस मामले सहित सभी में एक ही पैटर्न दिखाई देता है कि फ़ासीवादी सत्ता पीड़ितों को ही अपराधी साबित करने पर आमादा है। जो भी पीड़ितों व वंचितों के पक्ष में बोलने, लिखने अथवा साथ देने का साहस करता है, उन सबको अर्बन नक्सली व देशद्रोही करार करके फंसाया जा रहा है। हाथरस कवर करने जा रहे केरल के एक मीडियाकर्मी व उसके साथियों पर यूएपीए ठोक दिया गया है। इससे नागरिकों का जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार खतरे में पड़ गया है।

ध्यान रहे कि बुटाना कांड में मारे गए दोनों पुलिस वाले जाट समुदाय से हैंऔर बुटाना समेत बरौदा जाट बहुल क्षेत्र है, इसलिये बरौदा उपचुनाव के मद्देनज़र सभी राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है। आश्चर्य है कि वामपंथी दलों व इसके अन्य संगठनों तथा दलित समाज जिनका कुछ भी दांव पर नहीं है, वे भी चुप हैं।

कुछ उग्र हिंदुत्ववादियों के दबाव में आकर तनिष्क ज्वैलरी के मालिक ने उस विज्ञापन को हटाकर उसकी जगह शोरूम के दरवाजे पर हिंदुओं से माफ़ी मांगने वाला नोटिस चस्पा कर दिया। जबकि वास्तव में 'एकत्वम' विज्ञापन से हिन्दू-मुस्लिम आपसी समन्वय, प्यार व सच्चा सद्भाव प्रकट होता था।

देश की बदहाल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने व बाजार में मांग बढाने के नाम पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त त्योहारी एडवांस तथा एलटीसी वाउचर स्कीम की निरर्थकता की स्तम्भ 'खबर मरम्मत-निर्मला ताई ने फ़िर पकड़ाया झुनझुना' में समीक्षा की गई है।

विदित रहे कि त्योहारी एडवांस 10 किश्तों में वापिस लिया जायेगा, जिसे 30 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। एलटीसी के बदले में कैश वाउचर का विकल्प मिलेगा। जितना एलटीसी बनता है, उसका तीन गुना सामान डिजिटल मोड से खरीदना होगा और उसी सामान को खरीद सकेंगे जिस पर 12 प्रतिशत या ज्यादा जीएसटी लगता हो। जीएसटी नम्बर तथा जीएसटी के भुगतान वाला विक्रेता का बिल प्रस्तुत करना होगा। ये वाउचर भी 31 मार्च 2021 तक वैध होंगे। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे कर्मचारियों में से कोई गैर जरूरी सामान पर एलटीसी तथा उसकी तीन गुना धन राशि खर्च कर सकेगा इसमें संदेह है।

सरकारी कायदे कानून से अपने बिजनेस को बचाने के लिये राजनीतिक नेताओं और पूंजीपतियों का सदैव गठजोड़ रहा है। रतन टाटा और मुकेश अंबानी द्वारा उद्योग जगत को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के पीछे लामबंद करने के फ़लस्वरूप मोदी जी केन्द्र में सत्तारूढ़ हुए। लेकिन गुजरात में कच्छ ज़िले के गांधी धाम शहर में टाटा के तनिष्क ज्वैलरी के शोरूम पर हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने वाला 'एकत्वम' शीर्षक से जारी विज्ञापन लगाने पर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा इसे लवजिहाद को बढावा देने वाला एंटी हिंदू करार देकर मचाए गए बवाल को 'मासेदी से सवाल पूछ कर तो दिखाये रतन टाटा में उजागर किया गया है।